Mumbai Metro Transport Project

†4664-E. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHAUDAR: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government of Maharashtra has prepared a plan viz. Mumbai Metro Transport Project-2, for strengthening and augmenting the existing suburban transport;

(b) if so, whether the World Bank has agreed to cooperate in financing tre project; and

(c) whether the Maharashtra Government has requested the Central Government to help this suburban Railway Project Financially?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c) The Bombay Urban Transport Project-II was prepared by the BHRDA to augment the existing suburban railways and also to make improvements in the other road-based transport systems. The total cost of the Project at 1988-89 prices has been estimated at Rs. 2248 crores which include suburban railway component costing Rs. 1304,86 crores.

In view of the huge investment involved it has not been possible for the Govt. of India to provide funds for the project out of budgetary sources. The World Bank have indicated that they may consider the funding of the BUTP-II. Project if the railway component of the project can be funded from local resources.

The State Government have been requested to suggest a suitable financing package to fund the Railway component.

†Previously Unstarred Question 4095, transferred from 25th August, 1993.

कानून का उल्लंघन करके खनन गतिविधियां चलाया जाना

††4664.च **श्री महेश्वर सिंह** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने आमरु नामक स्थान के जो थारा घाटी, कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कुछ व्यक्तियों को ज्योति एंटरप्राइजेज के नाम से भुन्तर गड्सा रोड पर खनन कार्य करने की अनुमति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ज्योति एंटरप्राइजेज द्वारा किए जा रहे खनन कार्य से मोटर योग्य सड़क को खतरा उत्पन्न हो गया है और संबद्ध विभाग द्वारा खनन कार्य को रोकने का प्रयास किए जाने पर दूसरा पक्ष अदालत में चला गया ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस मामले में न्यायालय द्वारा प्रतिकूल फैसला दिए जाने के बावजूद सड़क के समीपवर्ती "थर्ड क्लास फारेस्ट लैंड" भूमि पर केन्द्रीय सरकार की आड़ लेकर खनन कार्य बिना किसी रोक-टोक के चलाया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार नियमों के विरुद्ध प्रदान की गई इस अनुमति को रद्द करेगी ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

††पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 4322, 26 अगस्त से स्थानांतरित ।